

प्रेषक,

आर० डी० पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 30 जनवरी, 2008

विषय:- जिला बागेश्वर में स्थापित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1-सात-जे/छत्तीस(1)/2006-176/01, दिनांक 18-02-2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिला बागेश्वर में स्थापित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय के लिए शासनादेश संख्या-4016/सात-न्याय-2-201/75, दिनांक 19-02-96 द्वारा सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 01-03-07 से दिनांक 28-02-09 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए०-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92, दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर० डी० पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 29(1) / XXXvi(2) / 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर ।
- 3- कार्मिक/नियुक्ति अनुभाग/वित्त अनुभाग-5 ।
- 4- एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।